**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 491**

**मंगलवार, 03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**धुले की औद्योगिक क्षमता**

**491. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के धुले जिले की प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर पर रणनीतिक स्थिति और एमआईडीसी औद्योगिक भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी औद्योगिक और संभार क्षमता संबंधी कोई व्यवहार्यता अध्ययन, क्षेत्रक आकलन, या योजना रिपोर्ट करवाई हैं या शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे आकलन की वर्तमान स्थिति क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या धुले और आस-पास के क्षेत्रों में भारी उद्योगों या विनिर्माण संकुलों के संवर्धन के लिए महाराष्ट्र सरकार, एमआईडीसी, या संभावित निवेशकों के साथ कोई परामर्श या चर्चा शुरू की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा, लॉजिस्टिक्स पार्क, या विनिर्माण संवर्धन से संबंधित केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत निवेश के लिए उपयुक्त के रूप में चिह्नित किए गए क्षेत्र, यदि कोई हों, कौन-से हैं; और

(ङ) क्या सरकार का धुले जिले में औद्योगिक निवेश और रोज़गार सृजन को आकर्षित करने के लिए समयबद्ध योजना या परियोजना-विकास कार्य करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री जितिन प्रसाद)**

**(क) और (ख):** उद्योग राज्य का विषय है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि धुले की लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक क्षमता इसकी उत्कृष्ट मल्टीमोडल कनेक्टिविटी से जुड़ी है, क्योंकि यह जिला एनएच-47, एनएच-52, एनएच-53, एनएच-46 और एनएच-60 के जंक्शन पर स्थित है। यह जिला कई राज्य राजमार्गों से जुड़ा हुआ है, जो इसे सहज रूप से ट्रांजिट और वितरण केंद्र बनाता है। इसकी माल ढुलाई की आवाजाही को डोंडाईचा रेलवे जंक्शन

द्वारा और सक्षम बनाया गया है, जबकि इसके निकट स्थित नासिक और शिरडी एयरपोर्ट, क्षेत्रीय एयर-कार्गो सहायता प्रदान करते हैं और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वैश्विक कनेक्टिविटी प्रदान करता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) और मुंबई पत्तन के माध्यम से समुद्री पहुंच, उत्तरी महाराष्ट्र के लिए निर्यात-आयात आवाजाही में धुले की भूमिका को सुदृढ़ करती है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आगे सूचित किया है कि इस अंतर्निहित कनेक्टिविटी क्षमता के आधार पर, महाराष्ट्र राज्य लॉजिस्टिक्स नीति, 2024, में धुले (नंदुरबार सहित) को जोन-2 में रखा गया है और एक क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स हब के विकास के लिए धुले-शिरपुर कॉरिडोर को चिह्नित किया है। यह नीति प्रत्येक जिले की जिला लॉजिस्टिक्स समन्वय समिति (डीएलसीसी) को लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के लिए उपयुक्त भूमि पार्सल को चिह्नित करने और उसका मूल्यांकन करने का अधिदेश देती है और इसका फोकस मुख्य रूप से इसका धुले के कॉरिडोर-आधारित लाभों का दोहन करना है।

**(ग):** महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) धुले और इसके आस-पास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न निवेश-संवर्धन कार्यकलाप और भावी निवेशकों के साथ निरंतर समन्वय करता है जिसमें सतत आउटरीच कार्यक्रम, सुविधा प्रदान करना और संवर्धनात्मक कार्यक्रम शामिल हैं।

वर्तमान में, नरदाना औद्योगिक क्षेत्र चरण-I में कई प्रमुख उद्योगों जैसे मैसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड, मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स रामा फॉस्फेट लिमिटेड और मैसर्स शिरपुर पावर (जिंदल) प्राइवेट लिमिटेड आदि को स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, नरदाना औद्योगिक क्षेत्र चरण-II में मैसर्स बेडमुथा वायर लिमिटेड, मैसर्स आर.एम. फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मयूरेश्वर सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड आदि को सहित प्रमुख औद्योगिक इकाइयों को स्थान दिया गया है।

**(घ) और (ङ):** जैसा कि राज्य द्वारा संसूचित किया गया है, धुले के वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य को कृषि-प्रसंस्करण, सीमेंट विनिर्माण, वस्त्र और लघु स्तर पर विनिर्माण जैसे क्षेत्रों द्वारा आकार दिया गया है, जिन्होंने पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र को प्रचालन के लिए उपयुक्त पाया है। इसके अलावा, एमआईडीसी ने धुले जिले में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए कई उपाय शुरू किए हैं, जिसमें उद्योग भरारी के तहत उद्योगजगत के साथ निरंतर सहभागिता संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं, जिसमें निवेशक से

संपर्क को सुगम बनाने, क्षेत्रगत अवसरों को चिह्नित करने और परियोजना स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम-काज पर फोकस किया गया है। महाराष्ट्र राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2024 के अनुरूप, एमआईडीसी, धुले जिले में प्रस्तावित लॉजिस्टिक्स पार्क की योजना और विकास के लिए विकास आयुक्त कार्यालय के साथ समन्वय करता है।

*****